Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 24-02-2006

Participants : Mohale Shri Punnulal

an>

Title : Need to merge National Rural Employment Scheme into Employment Guarantee Scheme.

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं भारत सरकार के ग्रामीण रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, न्यूनतम कार्यक्रम योजना, जवाहर रोजगार योजना एवं अन्य राट्रीय ग्रामीण योजना, जिनमें काम के बदले अनाज दिया जाता है, जैसे कार्य जो ग्राम तथा शहरों में स्वीकृत होते हैं, उसमें अधिकतर मिट्टी से संबंधित कार्य होते हैं जिसमें 70 प्रतिशत मजदूरों को देने में और 30 प्रतिशत अन्य कार्यों में खर्चा होता है। दूसरी ओर, जो पक्के निर्माण कार्य हैं, जैसे पक्की रोड, सड़क, पुल पुलिया, स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, संस्कार भवन, गोदाम, नाली निर्माण और गांवों में पचरी, नदी नालों में सीढ़ी बनती है, आदि कार्यों के लिए सरकार बहुत कम पैसा देती है। इन कार्यों के लिए पैसा नहीं मिलने के कारण ये रोजगार मूलक कार्य होते हैं। भारत सरकार ने रोजगार गारंटी योजना लागू की है, जिसमें प्रतिदिन 60 रुपया रोजी देने की गारंटी है। इन कार्यों को अगर कराते हैं, तो बरसात के दिनों में रोजगार गारंटी योजना में मिट्टी से संबंधित जो कार्य होते हैं, वे बह जाते हैं। उनके बहने के बाद उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, सिर्फ कुछ लोगों को रोजगार मिलता है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि रोजगार मूलक योजनाओं में, मैंने जो नाम गिनाये हैं, पक्के कार्यों को भी उसमें शामिल किया जाये, जिससे स्थायी रूप से गांवों में काम हो सके। इससे लोगों को 20-25 साल तक सुविधा हो जाएगी। यदि संस्कार भवन बनेगा, तो लोग नैतिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, अगर स्कूल बनेगा है तो वहां बच्चे पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत बनेगा. तो गांव के कार्यों को पंचायत देखेगी। इसी तरह जो महिला और पुरूा घाट बनते हैं,

उसमें स्नान करेंगे। ऐसे कार्य 20-40 साल तक टिकाऊ होंगे। मेरा कहना है कि सामान्य कामों को न करके, इन कार्यों को रोजगार गारंटी योजना में शामिल किया जाये, और उसमें जो अभी 40-20 का रेशियो है, वह 50-50 का रेशियो हो - मतलब उसमें इस रेश्यो में राशि दी जाये और काम के बदले अनाज मिले। इन कामों को स्वीकृति दी जाये। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि ऐसे कामों को राट्रीय कार्यक्रम योजना मे शामिल किया जाये, जिससे लोगों को रोजी-रोटी भी मिले और सुविधाएं भी मिलें, साथ ही पक्के निर्माण कार्य होने से गांव के

लोगों को फायदा होगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि राट्रीय ग्रामीण मूलक योजना में जितने कार्यक्रम है, उन्हें रोजगार गारंटी योजना में शामिल किया जाये।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on Monday, the 27th February, 2006.

18.30 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, February 27, 2006/Phalguna 8, 1927 (Saka).